संख्या-64-2025-I-1139537-डी-202-**38**-2-**2002-002-3-2024**

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक** 11 नवम्बर**, 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-147/लेखा-पैशन/डी०आर०डी०ए० (ग्रेच्युटी)/2025-26 लखनऊ, दिनांक 04 अगस्त, 2025 एवं पत्र संख्या-157/लेखा-पेंशन/डी०आर०डी०ए० (ग्रेच्युटी)/2025-26, दिनांक 02 सितम्बर 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रु० 1300.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु० 866.00 लाख (आठ करोड़ छाछठ लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु० 1300.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू० 866.00 लाख (रुपये आठ करोड़ छाछठ लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्य प्र०वि० का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न हीं यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, साम्य विकास उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यथावश्यक पैरा-94 की कार्यवाही आयुक्त. ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,66,00,000 (रुपये आठ करोड छाछठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 2501068000300 जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत कार्मिकों को रोच्युटी का भुगतान मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-2-71-X-2025-26 दिनांक 29-10-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव,

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 - महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प० प्रयागराज।
3- श्री चन्द्रिका प्रसाद, उपसचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त, याम्य विकास, उ० प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु 0-3
7- ग्राम्य विकास अनु०-3
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- गार्ड युक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।